

संपादकीय

वायु प्रदूषण

दीपावली के दिन पटाखों की आतिशाबाजी को पूर्ण प्रतिबंधित नहीं किया लेकिन जिस तरह की सीमाएं बना दी हैं, वे लागू हो जाएं तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से काफी हद तक मुक्त हो जाएंगे। रात के आठ से 10 बजे की समय-सीमा तो है ही। इसके साथ पटाखों की पिछले साल आवाज की जो तीव्रता निर्धारित की गई थी, वही रहेगी। किंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण पटाखों के निर्माण और उपयोग से सर्वाधित है। कुछ विभागों को अधिकार देना कि वो ध्यान रखें कि पटाखों के निर्माण में हानिकारक रसायनों का प्रयोग न हो, व्यावहारिक कदम है। मसलन, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोरेशन सेफ्टी आर्गनाइजेशन (पेसो) से कहा गया है कि पटाखों में अल्यूमिनियम की मात्रा पर विशेष ध्यान रखें। बैरियम रसायन पूरी तरह प्रतिबंधित है। अभी तक के अध्ययन में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वालों में इन दो रसायनों का नाम आया है। तो जो विभाग है उसे ही ध्यान रखना होगा। पेसो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। जिम्मेवारी उस पर है। लिथियम, आर्सेनिक, एंटिनमी (अंजन, सुरमा), सीसा और पारा युक्त पटाखे भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। साफ है कि अब इस तरह के पटाखों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। न्यायालय के आदेश के बाद अगर कंपनियां निर्माण करती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाइ हो सकती है।

पहले से बने हुए पटाखों में ये रसायन हैं, तो उनकी बिक्री दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं हो सकती। इसमें प्रतिबंधित पटाखे फोड़े जाने के लिए संबंधित इलाके के थाना प्रभारी को जिम्मेदार बनाया गया है। हालांकि थाना प्रभारी एक-एक गली में सिपाहियों को लगाकर कैसे पता कर सकेगा कि जो पटाखे छूट रहे हैं, वे प्रतिबंधित श्रेणी के हैं, या मान्य श्रेणी के? यह बड़ा प्रश्न है। बावजूद इसके हर कोई चाहता है कि हमारी आवोडवा इतनी स्वच्छ रहे कि मनुष्य सहित सारे जीव-जंतु आराम से सांस ले सकें। किसी तरह की बीमारी का शिकार न हों। आतिशबाजी की परंपरा हमारे यहां पुरानी है किंतु अगर आनंद में हम अपने लिए ही जहर फैलाने लगें तो उसको रोकना ही होगा। दीपावली उत्सव का एक लक्ष्य वायुमंडल को स्वच्छ करना भी है। हम जहरीले पटाखों द्वारा इस मूल लक्ष्य के विपरीत काम करते हैं। कम से कम उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ग्रीन पटाखों का निर्माण आरंभ होगा और इसके प्रयोग के भी हम अभ्यस्त हो जाएंगे। उसके बाद समय-सीमा की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।

विपक्षी गठबंधन

राहुल गांधी और उनके वरिष्ठ सहयोगियों को बोध हो चला है कि उनकी पार्टी अपने बूते 2019 का लोक सभा चुनाव जीत नहीं सकती। कांग्रेस के शीर्ष नेता समय-समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं। पहले सलमान खुर्शीद ने इस तरह का विचार प्रकट किया था। अब पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सफाई देने के अंदाज में कहा है कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से नहीं कहा है कि 2019 में विपक्षी गठबंधन सरकार बनाता है, तो राहुल ही प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका फैसला घटक दल करेंगे। कांग्रेसी नेताओं के विचार व्यावहारिक और वस्तुपरक हैं। जाहिर है कि सहयोगी दलों के प्रति कांग्रेस का रुख बदल रहा है। कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती जा रही है। 2014 के चुनाव में उसका प्रदर्शन सबसे खराब था। राज्यों में भी सिमटती जा रही है। कर्नाटक में जनता दल (एस) के नेतृत्व वाली सरकार में वह जूनियर पार्टनर है, जबकि उसकी सीटें ज्यादा हैं। सवाल है कि ऐसी स्थिति में वह अपने सहयोगी दलों का नेतृत्व कैसे कर सकती है? राहुल जानते हैं कि विपक्षी दलों में इस पद के कई दावेदार हैं। इसलिए उन्होंने चुनाव परिणाम आने तक इस मुद्दे पर विराम लगा दिया है। उनका सुझाव है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दल एक मंच पर आएं और चुनाव जीतने के बाद नेतृत्व का चयन हो। दरअसल, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है।

पूरे देश में उसकी उपस्थिति है। इसलिए उसके रणनीतिकारों को उम्मीद है कि विपक्षी खेमे में उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। ज्यादा सीटें जीतने वाला दल ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेगा। लेकिन क्या चुनाव पूर्व विपक्षी दलों का गठबंधन आकार ले पाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी इसी तरह का संकेत दिया है। कांग्रेस के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव एक अवसर था। वह मायावती के साथ समझौता करके नजीर पेश कर सकती थी। ममता बनर्जी की कांग्रेस के साथ किसी तरह के गठबंधन में उसकी दिलचस्पी नहीं है। सपा का रुख भी स्पष्ट नहीं है। सुनिश्चित है कि राजग को हराने के लिए विपक्ष की एकता जरूरी है। कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री पद कोई मुद्दा नहीं है, तो उसे समान विचारधारा वाले दलों को साझा मंच पर लाने के लिए बड़ा टिल टिघराना होगा जैसा कि उसने कर्नाटक में करके दिखाया है।

संक्षिप्त

गौर-चित्कोटी

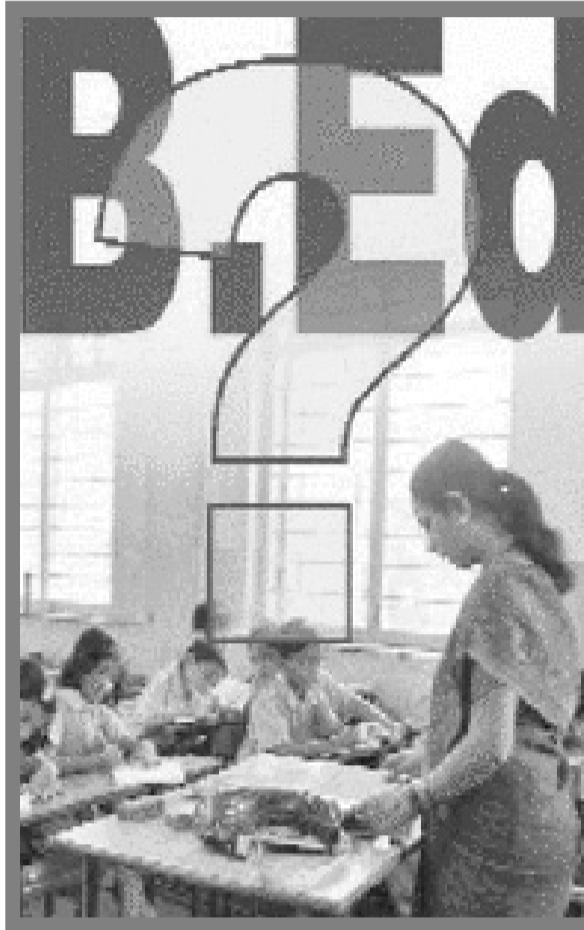
सांसारिक जीवन में किसी को शायद ही कुछ विशेष उपलब्ध हो पाता है। अपना सगा होते हुए भी एक पिता गैर-जिम्मेदार पुत्र को अपनी विपुल संपत्ति नहीं सौंपता। बाजार में विभिन्न तरह की वस्तुएं दुकानों में सजी होती हैं, पर उन्हें कोई मुफ्त में कहां प्राप्त कर पाता है? अनुनय-विनय करने वाले तो भीख जैसी नगण्य उपलब्धि ही करतलगत कर पाते हैं। पात्रता के आधार पर ही शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में भी विभिन्न स्तर की भौतिक उपलब्धियां हस्तगत करते सर्वत्र देखा जा सकता है। अध्यात्म क्षेत्र में भी यही सिद्धांत लागू होता है। पात्रता के अभाव में अधिकांश को दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों से वंचित रह जाना पड़ता है जबकि पात्रता विकसित हो जाने पर बिना मांगें साधक पर बरसती हैं। उन्हें किसी प्रकार का अनुनय-विनय नहीं करना पड़ता है। दैवी शक्तियां परीक्षा तो लेती हैं, पर पात्रता की कसौटी पर खरा सिद्ध होने वालों को मुक्तहस्त से अनुदान भी देती हैं। प्रकाश की ओर चलने पर छाया पीछे-पीछे अनुगमन करती है। अंधकार की दिशा में बढ़ने पर छाया आगे आ जाती है, उसे पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी वे पकड़ में नहीं आती। इसी प्रकार अर्थात् दिव्यता की ओर-श्रेष्ठता की ओर परमात्म पथ की ओर बढ़ने पर छाया अर्थात् ऋद्धि-सिद्धियां साधक के पीछे-पीछे चलने लगती हैं। इसके विपरीत उन्हीं की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर चलने पर तो आत्म-विकास की साधना से वंचित बने रहने से वे पकड़ में नहीं आतीं। दिव्यता की ओर बढ़ने का अर्थ है- अपने गुण, कर्म, स्वभाव को इतना परिष्कृत, परिमार्जित कर लेना कि आचरण में देवत्व प्रकट होने लगे। इच्छाएं, आकांक्षाएं देवस्तर की बन जाएं। संकीर्णता, स्वार्थपरता हेय और तुच्छ लगने लगे। समष्टि के कल्याण की इच्छा एवं उमंग उठे और उसी में अपना भी हित दिखाई दे। दूसरों का कष्ट, दुःख अपना ही जान पड़े और उनके निवारण के लिए मन मचलने लगे। सभी मनुष्य समस्त प्राणी अपनी ही सत्ता के अभिन्न अंग लगने लगें। आत्म विकास की इस स्थिति पर पहुंचे हुए साधक की, ऋद्धियां-सिद्धियां सहचरी बन जाती हैं। पर इन अलौकिक विभूतियों को प्राप्त करने के बाद वे उनका प्रयोग कभी भी अपने लिए अथवा संकीर्ण स्वार्थों के लिए नहीं करते। संसार के कल्याण के लिए ही उन शक्तियों का सहपर्योग करते हैं।

राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण परिषद

इस सोच के पीछे क्या शोध एवं मूल्यांकन पर आधारित कुछ तथ्य हैं, या यह परिकल्पना कि ज्यादा समय तक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रहने से अपने आप गुणवत्ता आ जाएगी? बेशक, गुणवत्ता के लिए कालावधि महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को कम करने वालों कारकों का विश्लेषण हमने किया है? क्या विश्लेषण के फलस्वरूप प्राप्त तथ्यों को हम आगे इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने देंगे? क्या प्रयोग के तौर पर बहुत पहले शुरू किए गए चार वर्षीय पाठ्यक्रम अधिक प्रभावशाली साबित हुए? और क्या तुलना में ऊपरका के बाद एकवर्षीय और फिर अब दो वर्षीय पाठ्यक्रम से हमने इसे अधिक बेहतर पाया है?

सतीश पेडणोकर

मंत्री के बजट भाषण से शुरू हुआ चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू करने का संकल्प अब केंद्रीय मानव-संसाधन विकास मंत्री के माध्यम से आगे बढ़ने लगा है। राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भी इसे मूर्त रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। लगता है 2019 से पूरे देश में एक साथ इसे लागू करने से शिक्षण की दशा रातोंतर सुधर जाएगी। इस सोच के पीछे क्या शोध एवं मूल्यांकन पर आधारित कुछ तथ्य हैं, या यह परिकल्पना कि ज्यादा समय तक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रहने से अपने आप गुणवत्ता आ जाएगी? बेशक, गुणवत्ता के लिए कालावधि महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को कम करने वालों कारकों का विश्लेषण हमने किया है? क्या विश्लेषण के फलस्वरूप प्राप्त तथ्यों को हम आगे इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने देंगे? क्या प्रयोग के तौर पर बहुत पहले शुरू किए गए चार वर्षीय पाठ्यक्रम अधिक प्रभावशाली साबित हुए? और क्या तुलना में स्तातक के बाद एकवर्षीय और पिछे अब दो वर्षीय पाठ्यक्रम से हमने इसे अधिक बेहतर पाया है? आज भी चार-वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम वाले क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों की तुलना में विद्यार्थी किसी विविदालय के शिक्षा विभाग या संकाय से योग्यता हासिल करने को प्राथमिकता देते हैं। दोनों प्रकार के संस्थानों की भी हमने तुलना नहीं की है, और अबलोकन के आधार पर तुलना करते हैं तो शिक्षा विभागों के विद्यार्थी को कमतर नहीं पाते हैं इन चार वर्षीय पाठ्यक्रम वाले संस्थानों से। अभी तो दो वर्षीय पाठ्यक्रम की समीक्षा और पिछे इसकी प्रभावकता की एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम से तुलना भी शेष है, पिछे देश किस परिवर्तन की अपेक्षा में इतना आतुर है? हमारे निर्णय का आधार तय जो शोध, मूल्यांकन, अबलोकन या पिछे समीक्षा से प्राप्त किया गया हो, होना चाहिए। हमें विद्यालयी शिक्षा को मजबूत कर उच्च शिक्षा को मजबूत करना होगा। इस दृष्टि से जरूरी है कि विद्यालयी शिक्षा, अध्यापक शिक्षा और पिछे अध्यापक शिक्षकों की शिक्षा में समन्वय हो। चतुर्थ वर्षीय पाठ्यक्रम को लागू करने के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं, वो मान्य नहीं हो सकते। यह गुणवत्ता के लिए हैं। यह पाठ्यक्रम एमबीबीएस, बीटेक और सीए को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। चतुर्थ वर्षीय पाठ्यक्रम से अध्यापक शिक्षा में सिर्फ सक्षम, गंभीर और योग्य शिक्षार्थी आएंगे। इस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षु ब्लूबैल चैलेंज, मनोवैज्ञानिक साइबर गेम्स और अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं को आसानी से हल कर सकने में योग्य बनेंगे। गुणवत्ता का संबंध गुणात्मक एवं मात्रात्मक जरूरत के अन्तः संबंध



को लागू करने की कोशिश की ? इन संस्तुतियों का अध्ययन या पिछे इनका मूल्यांकन किया ? यदि किया तो फिर शिक्षक को शिक्षाकर्मी क्यों बना दिया ? शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए जरूरी है योग्य शिक्षकों का निर्माण, जिन्हें हम सप्तम शिक्षा देकर दायित्व सौंपें। जरूरत आधारभूत संरचना को मजबूती देने की है, और जरूरत है अभिप्रेरित मानव-शक्ति की जो ईमानदारी से सभी निर्धारित जिम्मेवारी का निर्वहन करे। निर्माण और सशक्तिकरण हमारी शिक्षा का मूल-मंत्र होना चाहिए। तथा से भटके अनावश्यक प्रयोग खर्चीले तो होंगे पर जरूरी नहीं कि प्रभावकारी भी हों। ऐसे कदम शिक्षा की उचित भागीदारी वाली राष्ट्रीय बहस के बिना नहीं उठाए जाने चाहिए और इसे अंतिम रूप तब दिया जाना चाहिए। जब हम राष्ट्र को आस्त कर सकें कि यह कदम पूर्व की व्यवस्था से हर प्रकार से बेहतर विकल्प है। यह भी ध्यान रखना होगा कि स्नातक तक सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप विद्यार्थी के पास

अधिक विकल्प होते हैं, हमने राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी स्नातक ही योग्यता रखी है, महाविद्यालय और विविद्यालय में प्राधायापक बनने का रास्ता भी स्नातक तक सामान्य शिक्षा से ही जाता है। तो क्या विशिष्ट पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्ति और उस क्षेत्र में अवसर की कमी के कारण ऐसे शिक्षार्थी के लिए, कुछ अन्य अवसर कम नहीं हो जाएंगे ? वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में हमारा मूल-मंत्र सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, गैर-जरूरी परिवर्तन नहीं। विशिष्टता वाली शिक्षा तभी मेधावियों को आकर्षित करती है, जब उसमें आकर्षक अवसर और उसका व्यावसायिक मूल्य हों।

चलते चलते

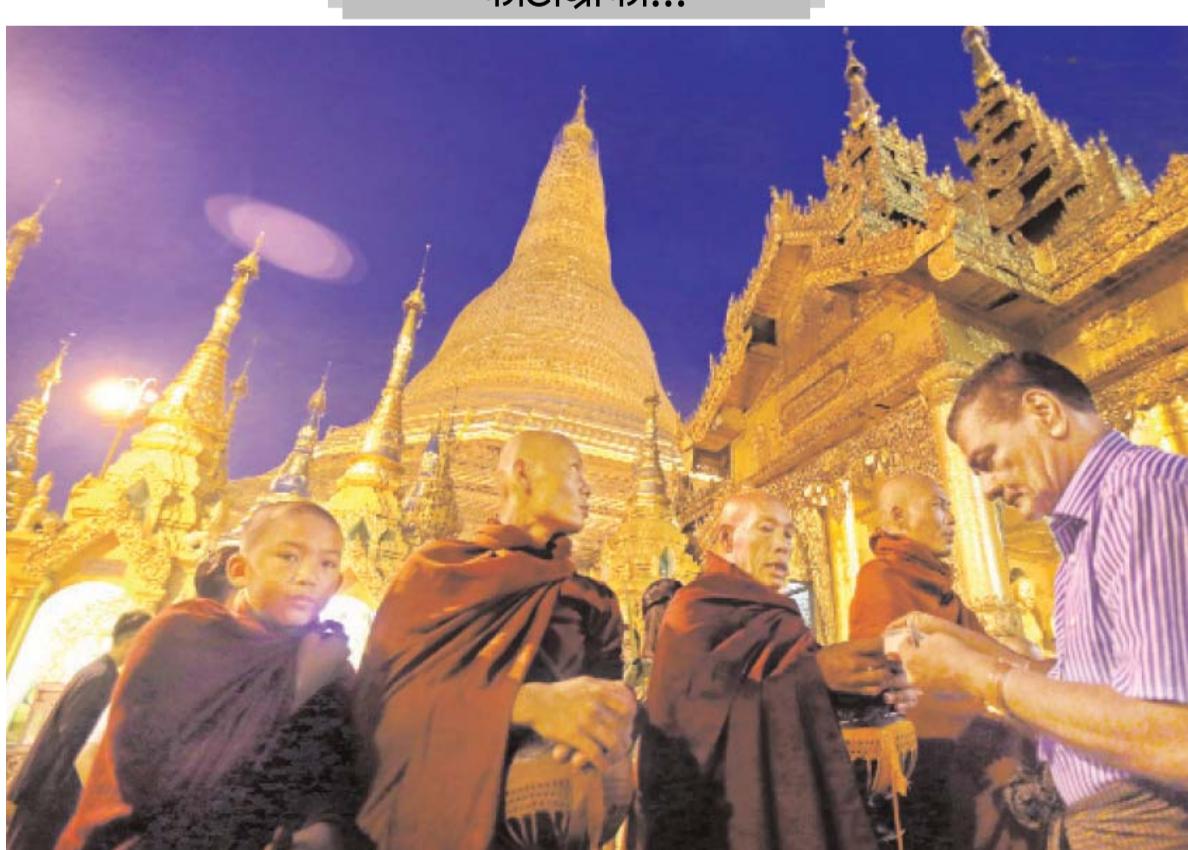
भ्रष्टाचार तलाशने की जरूरत ही नहीं

आत्मनिर्भर होने के मामले में शायद बीबीआई ही तमाम संस्थानों में सबसे आगे अब खुद उसके यहां इतना भ्रष्टाचार है उसे कहीं और भ्रष्टाचार तलाशने की व्यवस्था ही नहीं रही। सीबीआई डायरेक्टर इह रहे हैं कि स्पेशल डायरेक्टर भ्रष्ट हैं उन्हें यह कह कह रहा डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर के भ्रष्टाचार खोद-खोद कर निकाल रहा है, और शल डायरेक्टर उनके भ्रष्टाचार को। बीबीआई को अब किसी नेता, व्यापारी अधिकारी को गिरफ्तार करने की जरूरत है। गिरफ्तार करने के लिए खुद उसके इतने अधिकारी हैं। कहीं छापा डालने जरूरत नहीं। खुद अपने दफ्तर पर छापा डाल कर ही अब काफी संतुष्ट है। कहीं और फाइलें और कागज पत्र तलाशने जरूरत नहीं है। उम्म पर्याप्त कोई आगे प

र कह रहे हैं कि
ए है और स्पेशल
द रह है। डायरेक्टर,
भ्रष्टाचार को खोद-
ना है, और स्पेशल
वार को। सीबीआई
जेता, व्यापारी
इ काम नहीं कर रही।
के यह अधिकारी, उस
में लगा है, और वह
खिलाफ़। व्यस्तता की
पारोप नहीं लगा सकता
से ग्रस्त है। सरकार ने
जतना काम कर रही है,
एक-दूसरे के भ्रष्टाचार
दूसरे की टीमों के
न करें, अपने ही दफ्तर
नीबीआई दम गञ्जनीविक

हस्तक्षेप की कर्ताई परवाह नहीं कर रही। उस
पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि वह
अधिकारी एक दूसरे की मदद करते हैं। अब
भाई-भतीजावाद तो दूर, वहाँ तो अधिकारी भी
एक-दूसरे की मदद नहीं करते। उस पर कोई
पक्षपात करने का आरोप नहीं लगा सकता।
अब बताइए कि कोई भी जांच ऐसी इससे
ज्यादा तटस्थ और निरपेक्ष क्या रहेगी कि अपने
दफ्तर तक में छापामारी करने से गुरेज नहीं कर
रही। वह एक बार फिर छाती ठोंककर दावा कर
सकती है कि वह एक स्वतंत्र संगठन है। किसी
की परवाह नहीं करती। न सरकार की, न देश
की, किसी की नहीं। और तो और सीबीआई ने
तो प्रधानमंत्री तक को एक अच्छा मौका दे
दिया है। वे कह सकते हैं कि लोग मुझे तानाशाही
कहते हैं, देखो कितना झूठ कहते हैं। सीबीआई
के दो अफ्सर तक तो मेरे काबू में नहीं। कुछ
तो रहम कर्या याए।

फोटोग्राफी



यंगून : म्यांमार में शरद पूर्णिमा के दिन “थड़ींग्यूथ लान्टर्न” उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है इस दिन लोग सम्मान स्वरूप

प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने

अदालत द्वारा माहवारी आयु वर्ग की औरतों के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने के बावजूद अयप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को भीतर नहीं भुसने दिया गया। उग्र भीड़ ने जोर-जबरदस्ती से दर्शनार्थी स्त्रियों को बलपूर्वक रोका। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, पूजा करने के अधिकार का मतलब यह नहीं कि अपवित्र करने का अधिकार प्राप्त है। ईरानी ने कहा, यह साधारण सी बात है क्या आप माहवारी के खून से सना नैपकिन लेकर चलेंगे और किसी दोस्त के घर जाएंगे। आपको लगता है कि भगवान के घर ऐसे जाना सम्मानजनक है? यही पर्दा है। स्पष्ट रूप से उन्होंने दकियानूसी परंपरा का पक्ष लिया और वाहियात तर्क प्रस्तुत किया। पहली बात, श्रद्धालुओं में इतना शील-संकोच होता ही है कि वे अपने देवता के दर्शन के दरम्यान स्वच्छता का ख्याल स्वयं रखती हैं। वे कितनी ही खुले विचारों वाली हों, उनमें इतनी समझ है कि वे माहवारी के दौरान मंदिर प्रांगण में स्वतः ही नहीं जाती। दूसरे, आज भी लड़कियां/स्त्रियां देवताओं को जाने ही दें, देवियों के मंदिर में भी रजस्वला प्रवेश से झिझकती हैं। दूसरी बात, यह जो ईरानी ने तल्खी में बोली कि, खून से सना नैपकिन लेकर दोस्त के घर जाएंगी, यह स्तरहीन और स्त्रित्व का उपहास है। स्त्री होने के नाते, उन्हें अहसास होना चाहिए कि इस दौरान चलना-फिरना, यात्रा करना, देर तक टांगों को सिकोड़ कर रखना कितना कष्टकारी होता है। खासकर अपने यहां, जहां स्त्री के लिए मूर्त्रविसर्जन की सुविधाएं तक नहीं हैं। वह किसी आड़ में एकांत में भी बैठ नहीं सकती। ना ही पुरुषों की तरह, सड़क किनारे हल्की होने की हिमाकत कर सकती है। और तो और, कई दफ़ इसको फेंकने की भी दिक्कतें आती हैं। तो स्त्री मंदिर या देवता को अपवित्र कैसे कर सकती है? यहां तक की घर के भीतर के ठाकुरजी को भी स्त्रियां इस दरम्यान हाथ तक नहीं लगातीं। औरतों के मंदिर में प्रवेश को लेकर मचा यह घमासान स्त्रीविरोधियों के लिए अचूक अस्त्र साबित हो रहा है। चतुर पुरुषों ने स्त्रियों के प्रवेश में व्यवधान के लिए उन दकियानूसी औरतों का इस्तेमाल किया है, जिहें पुरुषों के बनाए नियम-कायदे पस्थर की लकीर लगते हैं। ईरानी का बयान भी कुछ इसी परंपरा की मिसाल है। स्त्री की देह से रिसने

वाला यह रक्त अव्वल तो अशुद्ध नहीं होता।
विज्ञान मनता है, यह शुद्ध रक्त होता है। जो स्त्री को उर्वर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। स्त्री की उर्वरता पर नतमस्तक होने की बजाए उसे तिरस्कृत करना, हमारे अज्ञान का आईना है। अव्वल तो आप धर्मभीरु हैं तो सभी धर्मों में जारी (कु)प्रथाओं की आलोचना से तौबा करनी चाहिए। स्त्री की समझ और उसके निर्णयों को चुनौती देने से बाज आने का वक्त आ चुका है। उसे आजादी चाहिए। उसे बराबरी का हक चाहिए। हर जगह। वह मंदिर हो, मजार हो या कोई सार्वजनिक स्थल। फ्लू के कारण देश में 542 लोगों को जान गंवानी पड़ी है द पिछले साल यह आंकड़ा 38,811 का था, जिसमें से 2,270 लोगों की मौत हुई थीं महाराष्ट्र में 14 अक्टूबर तक स्वाइन फ्लू के 1,793 मामले सामने आए हैं, इनमें 217 लोगों को जान गंवानी पड़ी है द इस सूची में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू के 1,912 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 191 लोगों की मौत हुई है द गुजरात में 1,478 स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए और 45 लोगों को जान गंवानी पड़ा द दिल्ली में 12 अक्टूबर तक 111 मामले सामने आए, जिनमें से एक की

